

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

इन्द्राराम पुत्र नैनाराम वगै. बनाम केसा पुत्र तुलछा वगै.

अपीलांत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम वास्ते  
निर्णय

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोंडेंट की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक:- 14.12.2021

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर अपीलांतगण के वकील द्वारा आपति पेश की गई। उस दिन अंतिम निर्णय व डिक्री जारी नहीं की गई। केवल मात्र वकील वादी की अंतिम बहस सुनी जाकर उसी दिन अपीलांत की गैर हाजरी में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। वर्तमान में जब उतरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलाधीन आराजी पर अपीलांतगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने व जबरन तारबन्दी करने लगा तब अपीलांतगण द्वारा मना करने पर नहीं माना। तथा कथन किया गया कि उक्त भूमि उसके न्यायालय की डिक्री से मिली है। जिस पर अपीलांतगण द्वारा वकील नियुक्त कर जानकारी प्राप्त की तब उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की दिनांक 14.08.2020 को नकले मांगी गई जो नकले तैयार होकर दिनांक 17.8.2020 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे। अपीलांत के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2014(1) Page 258

RRT 2012(1) Page 137

RRT 2004(1) Page 374

RRD 1998 Page 319

RRT 2002(1) Page 648

  
पुनः अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

RRT 2002(1) Page 53

RRT 2011(2) Page 1350

RRT 2017(2) Page 1104

अपील / डिक्री / टीए / 2818 व 2819 / 2019 / पाली

अपील / डिक्री / टीए / 2016 / 4893 व 4895 / श्रीगंगानगर

अपील / डिक्री / टीए / 1560 व 1651 / 2021 / पाली

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का जबाव पेश करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में बताया कि अपीलांटगण ने हस्तगत अपील स्थापित कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय व तथ्यों का सही विश्लेषण नहीं कर तथ्यों को छुपाते हुए अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन विधि विरुद्ध पेश किया है क्योंकि प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ 7 वर्ष बाद बिना कारणों का स्पष्टीकरण नहीं करते हुए अपील पेश की गई। अपीलांट के वकील ने विभाजन प्रस्ताव पर आपति अवश्य पेश की थी उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने आपति पर बहस सुनकर उसी दिन विधि व न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत विभाजन प्रस्ताव आने से अपीलांटगण ने बहस में सहयोग नहीं किया और रेस्पोंडेंट के वकील ने बहस सुनकर दिनांक 15.01.2013 को विधि व न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्तिम डिक्री जारी की उसका भली भांति अपीलांटगण मय वकील को अन्तिम डिक्री का ज्ञान होते हुए भी तथ्यों को तोड़मरोड़कर अपील को ज्ञान की तिथि से अन्दरम्याद लाने का प्रयास किया जो वाद कि बहुलता बढ़ाने के लिए व रेस्पोंडेंट को अपने हक-हकुको से महरूम रखने के लिए अपील पेश की गई। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

DNJ 2019 (SC) Page 1067

DNJ (Raj.)2020(3) Page 697


RRT 2018(1) Page 188

RRD 2017 Page 679

RRD 2017 Page 395

राजस्थान न्यायालय  
जयपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री दिनांक 15.01.2013 अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है हस्तगत अपील को सुदीर्घ अवधि तकरीबन 08 वर्ष 07 माह बाद पेश किया गया है जिसका कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। अपीलांट की अपीलों को इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है।

  
(अरविन्द कुमार जाखड़)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर